



प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले- संकट में भी जनता पर नहीं पड़ने दिया बोझ

(जीएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के बालोतरा में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण पैदा हुए 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का भारत ने यूपी चुनाव 2027: बीजेपी की महाबैठक में मिली जीत की चाबी? अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम योगी रहे शामिल



उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने अभी से अपनी रणनीति को थार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक अहम बैठक हुई। करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, जनाधार बढ़ाने और आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की।

लखनऊ के भाजपा कार्यालय में जोश हाई! नितिन नवीन का सीएम योगी और पंकज चौधरी ने किया स्वागत

(जीएनएस)। लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सुरक्षा के बीच रथ पर सवार होकर हजरतगंज स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं का जोश देखकर उत्साहित नजर आए। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर फूलों की माला फेंकी। साथ ही गुब्बारे आसमान में छोड़े।

अगले साल प्रस्तावित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को थार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार को अपने पहले दो दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर लखनऊ पहुंचे। खनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह,



प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान समेत राज्य सरकार के मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक करीब 18 किलोमीटर के मार्ग पर 50 से अधिक स्थानों पर उनका स्वागत किया गया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेष रथ पर सवार होकर रोड शो के लिए रवाना हुए। उनके साथ रथ पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद हैं। रोड शो के जरिए भाजपा राजधानी में शक्ति प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया। 9 दिन पहले के घोषित नई प्रदेश टीम के गठन के बाद

योजना, जयपुर मेट्रो विस्तार और शेखावटी जल परियोजना समेत कई विकास कार्यों का उल्लेख किया।

राजस्थान की विकास परियोजनाओं का किया उल्लेख

प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान की धरती ने हमेशा स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी और राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल, उड़ान योजना के नए चरण, जयपुर मेट्रो विस्तार और शेखावटी क्षेत्र की जल परियोजना जैसे कार्य राजस्थान के विकास को नई दिशा देंगे। उन्होंने 54 हजार युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र मिलने पर भी बधाई दी।

ऊर्जा संकट से निपटने की रणनीति बताई

पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण दुनिया ऊर्जा संकट से जुझ रही है, लेकिन भारत ने समय रहते सही निर्णय लेकर इस संकट का प्रभाव कम किया। उन्होंने कहा कि संकट के दौरान रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए

तैयार किया गया, जिससे सात दिनों के भीतर एलपीजी उत्पादन 35 हजार



मीट्रिक टन से बढ़कर 54 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गया। साथ ही पाइपड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन तेजी से बढ़ाए गए और कम समय में 11 लाख से अधिक घरों को पीएनजी से जोड़ा गया।

घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़ने दिया

प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध की परिस्थितियों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपए तक पहुंच सकती थी, लेकिन सरकार ने आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने दिया। उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी

सिलेंडर अब भी 900 रुपए से कम में उपलब्ध है, जबकि उज्ज्वला योजना के



लाभार्थियों को यह 650 रुपए से भी कम कीमत पर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने हाल ही में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बड़ी कटौती की है।

डीजल-पेट्रोल संकट और कूटनीति का किया जिक्र

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। इसके बावजूद भारत में ईंधन की आपूर्ति बाधित नहीं होने दी गई। उन्होंने कहा कि अप्रैल से जून के

बीच तेल कंपनियों ने 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक का घाटा उठाया, जबकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में प्रति लीटर 10 रुपए की कटौती कर आम जनता को राहत दी। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी कूटनीति के जरिए ईंधन आयात करने वाले देशों की संख्या 25-26 से बढ़ाकर 40 से अधिक कर दी।

रिफाइनरी क्षमता और कांग्रेस पर निशाना

प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी के लिए 2017 में समझौता हुआ था, लेकिन 2018 से 2023 तक राज्य में कांग्रेस सरकार के दौरान परियोजना की गति धीमी रही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद काम तेज हुआ और आज इसका लोकार्पण हो सका। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला देश बन चुका है और आने वाले वर्षों में यह क्षमता और बढ़ेगी।

किसानों और एमएसएमई के लिए उठाए गए कदम गिनाए

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद किसानों को 3,000 रुपए से अधिक कीमत वाली यूरिया की बोरी केवल 300 रुपए में

उपलब्ध कराई गई और इसके लिए सरकार ने भारी सब्सिडी दी। उन्होंने कहा कि उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की व्यवस्था की गई और घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया। साथ ही एमएसएमई क्षेत्र को राहत देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त ऋण और पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा पर जोर

पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत खेजड़ी का पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और यहां विश्वस्तरीय सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य में डेढ़ लाख से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा चुका है, जबकि पीएम कुसुम योजना के तहत 65 हजार से अधिक सोलर पंप किसानों को दिए गए हैं।

शेखावटी जल परियोजना का किया जिक्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा

सरकार ने राज्यों के बीच समन्वय से राजस्थान की जल समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए समझौते के तहत हथिनीकुंड बैराज से शेखावटी क्षेत्र तक पानी पहुंचाया जाएगा। लगभग 34 हजार करोड़ रुपए की इस परियोजना से सीकर, चूरू, झुंझुनूं, मेरठ, पुरी, शेखावटी क्षेत्र के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में अपर यमुना बेसिन की परियोजनाओं के पूरा होने पर राजस्थान को और अधिक पानी उपलब्ध होगा।

विकसित राजस्थान और विकसित भारत का संकल्प

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जयपुर मेट्रो फेज-2, जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाएं राजस्थान के विकास को नई गति देंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि डबल इंजन सरकार के सहयोग से राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और विकसित भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी मेलबर्न पुलिस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 जुलाई के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले मेलबर्न में आयोजित होने वाले कम्युनिटी प्रोग्राम को ऑनलाइन धमकी मिली है। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस मामले की जांच कर रही है और संदिग्ध सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े व्हट्सएप की पहचान भी कर चुकी है। (जीएनएस)।

नरेंद्र मोदी के 9 जुलाई को प्रस्तावित ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मेलबर्न में आयोजित होने वाले 'मेलबर्न मीट्स मोदी' कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी के बाद ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (AFP) ने जांच शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धमकी फेसबुक पर उस पोस्ट के नीचे दी गई थी, जिसमें मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में आयोजित होने वाले कम्युनिटी प्रोग्राम

का प्रचार किया जा रहा था। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का प्रमुख आकर्षण

बाद मामले को ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के पास भेज दिया गया। जांच एजेंसी ने व्हट्सएप की



माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 'अबू मुस्तफा' नाम के एक फेसबुक अकाउंट से टिप्पणी की गई, जिसमें लिखा था, 'बेहतर होगा कि कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम की छत बंद रहे, वरना वह ऑस्ट्रेलिया अपनी मौत के लिए आ रहे हैं।' इस पोस्ट के सामने आने के तुरंत

मामले में किसी आपराधिक कानून का उल्लंघन हुआ है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने अभी तक जांच को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन स्थानीय मीडिया का कहना है कि किसी भी विदेशी राष्ट्रध्यक्ष या सरकार प्रमुख को दी गई धमकी को ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसियां बेहद गंभीरता से लेती हैं। कई एजेंसियों के पास होगी पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी कई एजेंसियों के पास होगी, इसमें ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस, राज्य पुलिस और विशेष सुरक्षा इकाइयां शामिल रहेंगी। सभी कार्यक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जा रही है।

प्रधानमंत्री मोदी अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान द्विपक्षीय वाताओं में हिस्सा लेने के साथ-साथ भारतीय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत भर्ती करने से लेकर हमला करने तक, 23 और पाकिस्तानी कुख्यात अपराधियों को आतंकवादी किया घोषित

(जीएनएस)। केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी 'जोरो टॉलरेंस' नीति को और सख्त करते हुए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत 23 और कुख्यात अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। हाल के सालों में किसी एक सूची में इतने अधिक व्यक्तियों को आतंकवादी

घोषित करने की यह सबसे बड़ी कार्रवाईयों में से एक मानी जा रही है। गृह मंत्रालय का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से संचालित आतंकी नेटवर्क को कमजोर करना है। सूची में शामिल सभी आरोपी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और उनके सहयोगी संगठनों से जुड़े बताए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, ये लोग

भारत में आतंकी गतिविधियों, घुसपैठ और भर्ती जैसी साजिशों में शामिल रहे हैं। सरकार का मानना है कि इन 23 लोगों को UAPA की चौथी अनुसूची में शामिल करने से उनके नेटवर्क, फंडिंग और भर्ती करने वाले सिस्टम पर प्रभावी कार्रवाई करना आसान होगा। साल 2019 में UAPA में हुए संशोधन के बाद सरकार को सीधे किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला था।

इससे ऐसे लोगों के विनीय लेन-देन और गतिविधियों पर देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर रखना आसान हो जाता है। नई लिस्ट में मसूद इलियास कश्मीरी का नाम प्रमुख है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, वह आतंकियों की भर्ती, प्रशिक्षण और भारत में घुसपैठ करारों में शामिल रहा है। उसे 2022 में जम्मू के सुजवां सैन्य शिविर पर हुए हमले का मुख्य साजिशकर्ता भी माना जाता है।

इसके अलावा मोहम्मद मुसद्दीक को भी आतंकवादी घोषित किया गया है। उस पर सीमा पार से घुसपैठ करारों और सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती करने का आरोप है। वहीं मुप्ती मुहम्मद असगर खान पर 2016 के नगरोटा सेना शिविर हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिसमें 7 भारतीय जवान शहीद हुए थे। अब्दुल्लाह जिह्वादी का नाम भी सूची में शामिल है, जिस पर आतंकी शिविरों के संचालन और घुसपैठ करारों का आरोप है।

लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क पर भी शिकंजा

गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कई बड़े नामों पर भी कार्रवाई की है। इनमें फिदाईस अहमद भट पर जम्मू-कश्मीर में विदेशी आतंकियों को घुसपैठ और हथियारों की सप्लाई करारों का आरोप है। वहीं हाकून रशीद गनई पाकिस्तान से भारतीय युवाओं की भर्ती और हथियारों की व्यवस्था सभालता था।

सांसद अशोक मित्तल ने केतन अग्रवाल मर्डर केस के बाद राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की कर दी मांग

(जीएनएस)। पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की रहस्यमयी मौत का यह मामला अब केवल एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर न्याय की मांग के साथ शुरू हुई यह आवाज अब संसद की दहलीज तक पहुंच चुकी है। मंगेतर सिया गोयल द्वारा खौफनाक साजिश रचकर केतन अग्रवाल की हर् या के मामले के बाद पुरुष भयभीत हैं।

पुरुषों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर ये बेहद संवेदनशील मुद्दा संसद के उच्च सदन राज्यसभा में उठाया गया। राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने देश में 'राष्ट्रीय पुरुष आयोग' के गठन की जोरदार वकालत की। उन्होंने इस मांग के पीछे

मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुए केतन अग्रवाल की दुखद मौत का प्रमुख रूप से हवाला दिया।

सांसद अशोक मित्तल ने



शून्यकाल में ये मुद्दा उठाया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, पुणे का केतन अग्रवाल मामला बहुत परेशान करने वाला है। केतन और उनके परिवार को निष्पक्ष, पूरी और बिना किसी भेदभाव के जांच मिलनी चाहिए, और सबसे बढ़कर, उन्हें

न्याय मिलना चाहिए। मैंने संसद में 'नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल' पेश किया था। हर पीड़ित को न्याय, मदद और कानून के तहत समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। केतन का मामला यह याद दिलाता है कि पुरुष भी पीड़ित हो सकते हैं। उन्हें संस्थागत मदद, कानूनी सुरक्षा और एक ऐसा मंच मिलना चाहिए जहां उनकी बात सुनी जा सके। लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना, न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए।

अशोक मित्तल राज्यसभा सांसद हैं। अप्रैल 2022 से आम आदमी पार्टी से सांसद बने थे लेकिन 24 अप्रैल 2026 को डॉ. अशोक मित्तल ने राघव उनके परिवार को निष्पक्ष, पूरी और बिना किसी भेदभाव के जांच मिलनी चाहिए, और सबसे बढ़कर, उन्हें

सम्पादकीय

ईरान को जल्द मिलेंगे फंसे हुए अरबों डालर

ईरान-अमेरिका के युद्ध में कितनी तबाही हुई है, बताने की जरूरत नहीं है लेकिन संभव है कि ईरान को वास्तव में इस युद्ध से लाभ हो सकता है। यह मैं इसलिए कहा रहा हूं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने हाल ही में बड़ा ऐलान किया। दावा किया गया कि कतर में पंसी ईरान की 12 अरब डॉलर की राशि में से 6 अरब डॉलर जल्द जारी कर दिए जाएंगे।

कुम शहर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा ईरान-अमेरिका डील के तहत असेट रिलीज करने की पहली किश्त होगी जो उसे कतर से मिलेगी। उन्होंने यह महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता और इस्लामाबाद में हुए समझौते के तहत यह राशि रिलीज हो रही है। बाकी 6 अरब डॉलर की वापसी के लिए भी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। पेजेशकियन ने बताया कि शांति समझौते के तहत ईरान के तेल और पेट्रोलैमिक क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।

उन्होंने इसे ईरानी जनता की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों के हटने से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिलेगी। ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर ने राष्ट्रपति के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राष्ट्रपति ने हाल के संघर्ष का जिक्र करते हुए ईरानी जनता की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुप्रिम लीडर, मंत्री, सेना कमांडर, बुद्धिजीवी और आम नागरिक भी संकट के समय एकजुट रहे। राष्ट्रपति ने बताया कि संघर्ष के बाद सरकार पुर्ननिर्माण कार्य शुरू कर चुकी है। आम लोगों को रहात देने के लिए खादा सब्सिडी बढ़ाने और अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। ईरान के इस दावे से उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था को वुछ राहत मिलेगी। कतर में पंसा पैसा रिलीज होने से तेल निर्यात और अन्य क्षेत्रों में सुधार आ सकता है।

यह घटनाम ईरान की विदेश नीति और आर्थिक रणनीतिक में नई दिशा दिखाता है, हालांकि अब तक ईरान में होने वाले 300 बिलियन डॉलर के निवेश को लेकर कोई बात साफ नहीं हुई है। ये पंड कहाा से आएगा, कब आएगा इस पर वुछ नहीं कहा गया।

विदेशों में ईरान की वुल जब् या प्रतिबंधित संपत्ति का अनुमान लगभग 100 अरब डॉलर है। इस प्रतिबंधित खातों में तेल से होने वाली कमाई, विदेशी मुद्रा भंडार, बैंकिंग संपत्ति व अन्य दावे शामिल हैं। पहली बार बड़े पैमाने पर संपत्ति तब प्रीज की गई, जब ईरान में इस्लामिक त्रांति हुई और अमरीरकी दूतावास में बंधक संकट पैदा हुआ। 14 नवम्बर 1979 को ईरानी त्रांतिकारियों द्वारा तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में मौजूद ईरानी सरकार की संपत्ति को ब्लॉक कर दिया। 1980 में ईरान सरकार की लगभग 12 अरब डॉलर की संपत्ति जव्त की गई थी जो ज्यादातर अमेरिकी बैंकों में थी। इसमें नकद, सोना, कई अन्य होल्डिंग्स शामिल थी। इसमें से अधिकांश संपत्ति 1981 के अल्जीयरस समझौते के तहत जारी कर दी गई थी, जिससे बंधक संकट समाप्त हुआ था। लगभग 4 महीने के युद्ध के बाद अमेरिका-ईरान शांति समझौते की रूपरेखा पर सहमत हुए हैं। इसके बावजूद ईरान की जव्त संपत्तियों पर अड़चन बनी हुई है। एक तरफ ईरान ने 14 सूत्री समझौते के हवाले से रिपोर्ट दी है कि अमेरिका बातचीत शुरू होने से पहले जव्त संपत्ति जारी करने पर सहमत हो। पर ट्रंप के कई बार विरोधाभासी बयानों ने स्थिति को असमंजस में डाल रखा है।

वैभव सूर्यवंशी नहीं सबसे युवा डेब्यूटेंट, कौन है वह पाकिस्तानी जिसने 14 साल में खेला पहला इंटरनेशनल गेम ?

(जीएनएस)।

भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में जब 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया की जर्सी पहनकर मैदान पर कदम रखा, तो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। बिहार के समस्तीपुर से निकलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने वाले इस युवा बल्लेबाज ने डेब्यू के साथ ही सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया और भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। उनकी इस उपलब्धि से पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई।

हालांकि वैभव सूर्यवंशी की यह उपलब्धि जितनी बड़ी है, उतनी ही दिलचस्प एक और सच्चाई भी है। भारत का रिकॉर्ड अपने नाम करने के

बावजूद वह विश्व क्रिकेट के सबसे



युवा इंटरनेशनल डेब्यूटेंट नहीं बन सके। यह रिकॉर्ड आज भी पाकिस्तान के एक क्रिकेटर के नाम दर्ज है, जिसने महज 14 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखकर इतिहास रचा था।

कौन है यह पाकिस्तानी खिलाड़ी ?

विश्व क्रिकेट में सबसे कम उम्र



युवा इंटरनेशनल डेब्यूटेंट नहीं बन सके। यह रिकॉर्ड आज भी पाकिस्तान के एक क्रिकेटर के नाम दर्ज है, जिसने महज 14 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखकर इतिहास रचा था।

57 साल की हिंदू एक्ट्रेस की शादीशुदा मुस्लिम म्यूजिक कंपोजर ने बर्बाद की जिंदगी, दर्दनाक बना करियर

(जीएनएस)।

बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाए बिना भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। प्रतिभा सिन्हा भी उन्हीं नामों में शामिल हैं। फिल्मों में लंबी पारी भले ही न खेल पाईं लेकिन एक गाने ने उन्हें ऐसी पॉपुलैरिटी दिलाई कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं।

एक सुपरहिट गाने ने बदल दी थी पहचान

4 जुलाई 1969 को कोलकाता में जन्मी प्रतिभा सिन्हा मशहूर एक्ट्रेस माला सिन्हा (टें' रल्लैं) की बेटी हैं। आज प्रतिभा सिन्हा का 57वां जन्मदिन है। फिल्मी माहौल में पली-बढ़ी प्रतिभा सिन्हा ने भी अपनी मां की तरह फिल्मी दुनिया में कदम रखा और इस जगत में सफलता हासिल करने का सपना देखा। हालांकि उनकी मॉजिल वैसी नहीं रही जैसी उन्होंने कल्पना की थी।

बॉलीवुड में रखा कदम लेकिन किस्मत ने नहीं दिया साथ

–प्रतिभा सिन्हा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म 'महबूब मेरे महबूब' से की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन वह पहचान हासिल नहीं कर सकीं जिसकी उन्हें उम्मीद थी।

–प्रतिभा सिन्हा के करियर का सबसे यादगार मोड़ साल 1996 में आया, जब फिल्म राजा हिंदुस्तानी (फ्रं छल्लेश्रिर्इल्ल) का गाना 'परदेसी-परदेसी' रिलीज हुआ था। इस गाने में प्रतिभा की मौजूदगी भले ही सीमित थी लेकिन उनके एक्सीशन्य, अंदाज और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया था। देखते ही देखते वह चर्चा का विषय बन गईं और उन्हें नई पहचान मिल गई। इस गाने ने उन्हें रातोरात स्टार बना दिया था।

मुस्लिम म्यूजिक कंपोजर ने बर्बाद कर दी प्रतिभा की जिंदगी

–फिल्मी सफर के साथ-साथ प्रतिभा सिन्हा की निजी जिंदगी भी लंबे समय तक खबरों में बनी रही। उस दौर में प्रतिभा सिन्हा का नाम बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक कंपोजर नदीम सैफी (टीवी श्रं) के साथ जोड़ा गया था। दोनों के रिश्ते को लेकर मीडिया में कई तरह की चर्चाएं होती थीं।

–बताया जाता है कि प्रतिभा सिन्हा की मां माला सिन्हा को नदीम के साथ उनकी बेटी का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। दरअसल नदीम सैफी पहले से शादीशुदा थे। समय के साथ इस रिश्ते को लेकर कई विवाद और अफवाहें सामने आईं, जिनकी चर्चा फिल्मी गलियारों में लंबे समय तक होती रही।

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले लखनऊ का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. अयोध्या में चढ़ावा कांड के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंच गए हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ सहित राज्य के दोनों डिप्टी सीएम ने एयरपोर्ट पर नितिन नवीन का स्वागत किया. इस दौरान सीएम योगी ने सबसे पहले नितिन नवीन के गले में भगवा पटका पहनाया. इसके बाद दोनों ने मंद-मंद मुस्कराया. दोनों की इस मुस्कराहट बता रहा है कि यूपी चुनाव 2027 के लिए चक्रव्यूह की रचना दिल्ली से लखनऊ पहुंच गया है. (जीएनएस)।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी भले ही दूर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर अपनी गोटियां सेंट करना शुरू कर

दिया है. इसी सिलसिले में शनिवार को देश की सियासत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेहद खास और अहम हलचल देखने को मिली. दिल्ली की सियासी गलियारों से निकलकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय सांगठनिक दौरे पर सीधे नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे हैं.

हवाई अड्डे पर जब नितिन नवीन उतरे, तो उनके सीएम योगी ने सबसे पहले उनके गले में चमचमाता हुआ भगवा पटका पहनाया. दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी गहरी मुस्कान थी. खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेहद भव्य और जोशीला स्वागत किया. इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे.

योगी-नवीन की मुलाकात के राजनीतिक मायने इस खास मुलाकात के बाद

ईशा मालवीय ने पीएम मोदी के हमशक्ल को समझ लिया असली प्रधानमंत्री, झुककर किया नमस्ते तो छूटी सबकी हंसी

ईशा मालवीय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के हमशक्ल को असली मोदी जी समझ लिया और उन्हें झुककर नमस्ते भी कहने लगीं। ईशा के रिएक्शन को लेकर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर टीवी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' फेम ईशा मालवीय का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। मुंबई में एक पब्लिक इवेंट के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल को कुछ पल के लिए असली प्रधानमंत्री समझ लिया। यह घटना एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान हुई, जहां ईशा रेड कार्पेट पर मीडिया और

मेहमानों से बातचीत कर रही थीं। ऑनलाइन वायरल हो रहे एक वीडियो में एक्ट्रेस को हैरानी से रिएक्शन देते हुए देखा जा सकता है, जब उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा दिखता था।

जैसे ही उनकी नजर उस आदमी पर पड़ी, ईशा मालवीय चौंक गईं और मुस्कराते हुए बोलीं, 'ओह, मोदी जी!' उनके इस रिएक्शन पर वहां मौजूद लोगों की हंसी छूट पड़ी। कुछ ही पल बाद, एक्ट्रेस को एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि उनका हमशक्ल है। उन्होंने इस स्थिति को मजाकिया अंदाज में लिया, उस व्यक्ति से हाथ मिलाया और फोटो के लिए पोज

सियासी गलियारों में यह साफ मैसेज चला गया है कि बीजेपी आलाकमान और सीएम योगी की यह जोड़ी आगामी यूपी चुनाव 2027 के लिए



एक अभेद्य किला तैयार करने में जुट गई है. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश में यह दूसरा दौरा है, इससे पहले वह पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम में मथुरा में सीएम योगी के साथ मंच शेयर कर चुके हैं. लेकिन अब यूपी

चुनाव 2027 के लिए प्रदेश की नई सांगठनिक टीम के गठन के तुरंत बाद यह दौरा हो रहा है. उनके इस मुस्कराते हुए चेहरे और भगवा पट्टे के

पीछे एक बेहद मजबूत और कड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है. योगी और नवीन की जोड़ी की क्या है तैयारी? पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश संगठन और सरकार के बीच चल रही कथित अनबन की अटकलों को इस

दिया। कैमरे की ओर देखते हुए उन्होंने मजाक में कहा, 'दोस्तों, हमारे

वीडियो में दिखने वाले व्यक्ति विकास महंते हैं, जो मुंबई के एक

कई पॉलिटिकल कैंपेन इवेंट्स और पब्लिक प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया



साथ मोदी जी हैं।'

ईशा मालवीय की क्लिप यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने इस घटना पर मजेदार रिएक्शन्स दिए। कई लोगों ने मुस्कराते हुए स्थिति को संभालने के लिए ईशा की तारीफ की, जबकि कुछ लोगों ने उस जबरदस्त समानता पर कमेंट किया जिसकी वजह से यह कन्स्प्यूजन हुआ। कौन है विकास महंते ?

बिजनेसमैन, एक्टर और सोशल वर्कर हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शक्ल-सूरत के लिए काफी मशहूर हैं। पिछले कुछ सालों में, महंते ने अपने लुक, दाढ़ी के स्टाइल और तौर-तरीकों की वजह से पब्लिक इवेंट्स में लोगों का ध्यान खींचा है। कई लोगों को उनकी हरकतें प्रधानमंत्री जैसी ही लगती हैं।

विकास महंते की फिल्में महंते ने अलग-अलग राज्यों में

क्या बैन हो गई सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' ? सेंसर ने लगा दी रोक ? मेकर्स ने सामने रखा ऐसा सच

(जीएनएस)।

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मातृभूमि' इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। हालांकि इस बार वजह फिल्म के कहानी या स्टारकास्ट नहीं बल्कि उससे जुड़ी वो खबरें हैं जिनमें दावा किया जा रहा था कि फिल्म को सेंसर

बोर्ड से मंजूरी मिलने में परेशानी आ रही है।

'मातृभूमि' को लेकर फैली अफवाहों पर आया आधिकारिक बयान इन चर्चाओं ने सोशल मीडिया पर तेजी से जोर पकड़ा, जिसके बाद

भरोसा नहीं करना चाहिए।

अभी सेंसर बोर्ड के पास पहुंची ही नहीं फिल्म निमाताओं द्वारा शेयर किए गए बयान में ये भी बताया गया कि 'मातृभूमि' को अभी तक प्रमाणन प्रक्रिया के लिए सेंसर बोर्ड के पास

लगाना और दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचाना है।

देशभक्ति के रंग में नजर आएंगे सलमान खान

'मातृभूमि' को एक देशभक्ति से प्रेरित फिल्म बताया जा रहा है। फिल्म में सलमान खान एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाते नजर आएंगे।



दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। लेकिन अब इन अफवाहों पर निमाताओं ने खुद सामने आकर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

सलमान खान फिल्म्स ने जारी किया स्पष्टीकरण

फिल्म के प्रोडक्शन हाउस Salman Khan Films ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन सभी रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत बताया गया है, जिनमें कहा जा रहा था कि फिल्म का सर्टिफिकेशन रोक दिया गया है या उसे किसी तरह की सेंसर संबंधी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। निमाताओं ने स्पष्ट किया कि फिल्म को लेकर फैल रही ऐसी खबरों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और दर्शकों को अयुष्ट जानकारी पर

भेजा ही नहीं गया है। ऐसे में फिल्म के सर्टिफिकेशन को रोकें जाने या किसी तरह की आपत्ति लगाए जाने की बातें पूरी तरह निराधार हैं। इस स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया है कि सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में चल रही अटकलें महज अफवाह थीं और फिल्म फिलहाल अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है।

फैंस से की गई खास अपील

सलमान खान प्रोडक्शन हाउस ने दर्शकों और मीडिया से ये भी अनुरोध किया है कि फिल्म से जुड़ी किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। निमाताओं का कहना है कि मातृभूमि से संबंधित सभी आधिकारिक अपडेट केवल उनके अधिकृत प्लेटफॉर्मों से। माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। इस अपील का मकसद फिल्म को लेकर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर रोक

आगामी तीन दिनों के रोडमैप पर मुख्य रूप से इन 3 बड़े बिंदुओं पर चक्रव्यूह रचा जा रहा है:

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ के राज्य मुख्यालय में नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ-साथ 'शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन' को भी संबोधित करेंगे. बीजेपी का पुराना नारा रहा है, 'बृथ जीता तो चुनाव जीता'. लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों से सबक लेते हुए, बीजेपी इस बार अति-आत्मविश्वास से बचकर हर छोटे मोर्चे पर बारीकी से काम कर रही है.

पार्टी सूत्रों का कहना है 'नितिन नवीन का यह दो दिवसीय दौरा यूपी के कार्यकाताओं में वह 'इलेक्ट्रिक एनर्जी' भरने आया है जिसकी जरूरत आगामी चुनावी जंग के लिए है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरी रणनीति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मंत्रियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे जिलों में कैंप करें और सीधे जनता से फीडबैक लें.'

है। इसके अलावा, वह 'मोदी काका का गांव', 'द साबरमती रिपोर्ट', और 'एक नया सवेरा' जैसे प्रोजेक्ट्स से भी जुड़े रहे हैं।

ईशा मालवीय कौन हैं ? वहीं, ईशा मालवीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक पॉपुलर चेहरा बनी हुई हैं। उन्होंने कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और 'मिस मध्य प्रदेश' समेत कई ब्यूटी पेजेंट के खिताब जीते। उनके एक्टिंग करियर को टीवी शो 'उड़ारिया' से रफ्तार मिली, जिसमें जैस्मीन कौर संधू के किरदार में उन्हें काफी पहचान मिली। भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो में से एक 'बिग बॉस 17' में हिस्सा लेने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई।

इंटरनेट पर वायरल है वीडियो हालांकि यह वायरल वीडियो सिर्फ कुछ सेकंड का था, लेकिन ईशा के तुरंत रिएक्शन और उस आदमी की प्रधानमंत्री से हैरान कर देने वाली मिलती-जुलती शक्ल (जिसे उन्होंने शुरू में प्रधानमंत्री समझा था) की वजह से यह ऑनलाइन सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले एंटरटेनमेंट क्लिप्स में से एक बन गया है।

चंपत राय के समर्थन में उतरे अयोध्या के साधु-संत, राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे को लेकर की ये अपील

राम मंदिर दान चोरी मामले में इस्तीफा देने वाले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में साधु-संत उतर आए हैं। उन्होंने ट्रस्ट से इस्तीफा न स्वीकार करने की अपील की है।

(जीएनएस)। अयोध्या: अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर जारी विवाद के बीच शनिवार को संत समाज उनके समर्थन में उतर आया। संतों ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से अपील की कि वह चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार न करे। अयोध्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संतों ने चंपत राय की ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उनका मकसद उनकी सार्वजनिक छवि को खराब करना है।

पारदर्शी व्यवहार की बात अयोध्या के संतों ने कहा कि चंपत राय दशकों से राम मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण से गहराई से जुड़े रहे हैं। उनका सार्वजनिक जीवन पारदर्शिता और समर्पण से भरा रहा है। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है और यह उन्हें बदनाम करने की एक अनावश्यक कोशिश है।

अयोध्या में राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने महिला को दी नई जिंदगी, ऑपरेशन कर पेट से निकाला 10 किलो का द्यूमर

(जीएनएस)। अयोध्या। राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज, दर्शननगर के चिकित्सकों ने महिला के पेट से दस किलो का द्यूमर ऑपरेशन करके निकाला है। महिला गोंडा जिले की मनकापुर निवासी है। वह पांच वर्षों से उपचार गोंडा में ही करा रही थी। महिला को शुरूआती दौर में 500 ग्राम का द्यूमर होने की जानकारी मिल थी। उपचार आरंभ होने के बाद पांच वर्षों में बढ़कर दस किलो पहुंच गया। हालत बिगड़ने पर आठ जून को मेडिकल कॉलेज में पहुंची थी। ओपीडी में जर्मन सर्जन डॉ. प्रदीप सिंह ने भर्ती कर जांच कराई और शुक्रवार को विभागाध्यक्ष डॉ. एमसी पांडेय की निगरानी में डॉ. प्रदीप ने ऑपरेशन किया। महिला पूरी तरह स्वस्थ है।

मनकापुर बाजार निवासी प्रमोद

संतों ने कहा कि इस विवाद के दौरान चंपत राय का व्यवहार पूरी तरह पारदर्शी रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाने की मांग की थी, जिससे यह साबित होता है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और उन्हें पूरी जांच से कोई आपत्ति नहीं है।

एसआईटी बनाने का स्वागत एसआईटी बनाने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए संतों ने कहा कि जांच से सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विवाद के बावजूद चंपत राय ने संयम बरता और सार्वजनिक बयान देने से बचे। उनके प्रति एकजुटता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या के संत मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। उन्हें आरोप बेबुनियाद हैं। उनका मकसद उनकी सार्वजनिक छवि को खराब करना है।

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान संतों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के सामने कई सवाल भी उठाए। उन्होंने मंदिर के फंड की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों पर सवाल उठाए और जानना चाहा कि पर्याप्त सावधानी क्यों नहीं बरती गई।

बैठक पहले बुलाने पर सवाल संतों ने यह भी पूछा कि ट्रस्ट की प्रस्तावित बैठक समय से पहले क्यों बुलाई गई और इस फैसले की क्या



जेरूरत थी। संतों ने मांग की कि ट्रस्ट इन मुद्दों पर स्पष्ट जवाब दे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है और भ्रम और विवाद से बचने के लिए मंदिर से जुड़े सभी मामलों में पूरी पारदर्शिता जरूरी है। बाद में कई संतों ने चंपत राय के लिए अपना समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

संत राघवेश दास वेदांती ने कहा कि अयोध्या के संत ट्रस्ट से मांग कर रहे हैं कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार न किया जाए। एसआईटी ने जिन आरोपियों को पकड़ा है, उन्हें रिमांड पर लिया गया है। कुछ दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी और सब कुछ साफ हो जाएगा।

चंपत पर आरोप बेबुनियाद राम कचहरी मंदिर के महंत शशिकांत दास ने बताया कि चंपत को दोषी ठहराया जा रहा है, जो पूरी तरह

दिया। डॉ. श्रृष्टे ने बताया कि भर्ती करने के बाद सबसे पहले जांच में कैसर की आशंका दूर करने के लिए सैपल भेज अस्पताल से संबंधित दूसरी जांच और ब्लड की कमी को दूर करने के लिए उपचार चलता रहा। शुक्रवार को सभी रिपोर्ट नार्मल होने पर डॉ. प्रदीप सिंह ने डॉ. दिव्या उपाध्याय, डॉ. श्रृष्टे तिवारी, डॉ. पीयूष कांत और बेहोशी की डॉ. नेहा सिंह तथा डॉ. अमन के साथ मिलकर ऑपरेशन कर दिया। द्यूमर के साथ करीब तीन से चार लीटर पानी भी निकला।

मेडिकल कॉलेज के सभी विभागों के डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। जनरल सर्जनों का बहुत ही सराहनीय प्रयास चल रहा है। उनके इसी प्रयास से जनता को काफी राहत मिल रही है।

– डॉ. दिनेश सिंह मातोँलिया, प्राचार्य

अयोध्या में 5.61 लाख के केसीसी बकाया पर किसान के खेत की कुर्की, प्रशासन ने लगाई लाल झंडी

अयोध्या में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के 5.61 लाख रुपये के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का भुगतान न करने पर तहसील प्रशासन ने एक किसान के खेत की कुर्की कर दी .

(जीएनएस)। शुजागंज (अयोध्या)। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा मवाई से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत लिया गया 5.61 लाख रुपये का ऋण न चुकाने पर तहसील प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बकायेदार किसान के खेत की कुर्की कर दी। राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में खेत पर लाल झंडी लगाकर कुर्की आदेश का पालन कराया गया।

मवाई थाना क्षेत्र के ग्राम ओहगामऊ सहजना निवासी राज कुमार पुत्र काशीराम पर बैंक के अनुसार 5,61,544 रुपये का बकाया था। बैंक द्वारा कई बार नोटिस जारी कर भुगतान का अवसर दिए जाने के बावजूद राशि जमा न होने पर राजस्व वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई। सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बाद तहसील प्रशासन ने खेत की कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई।

कार्रवाई के दौरान तहसीलदार विजय कुमार, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा मवाई के शाखा प्रबंधक रोहित श्रीवास्तव तथा मवाई पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अधिकारियों ने खेत

पर लाल झंडी लगाकर कुर्की की औपचारिक प्रक्रिया पूरी कराई।

शाखा प्रबंधक रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि बकाया राशि का भुगतान होने तक नियमानुसार आगे की राजस्व वसूली की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने किसानों से समय पर ऋण अदायगी करने की

आर्थिक तंगी नहीं बनेगी बाधा! 865 होनहारों को सरकार देगी फ्री हॉस्टल, किताबें और टॉप क्लास कोचिंग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में यूपी सरकार ने SC, ST और OBC के गरीब व होनहार युवाओं के लिए 'निःशुल्क आईएएस-पीसीएस आवासीय कोचिंग योजना' शुरू की है निःशुल्क आईएएस-पीसीएस कोचिंग योजना से बदलेगा यूपी के होनहारों का भविष्य यूपी सरकार की निःशुल्क आईएएस-पीसीएस आवासीय कोचिंग योजना।

865 छात्रों को मुफ्त रहना, खाना और उच्च स्तरीय कोचिंग। प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई 2026 को, कक्षाएं 1 अगस्त से। (जीएनएस)। **लखनऊ।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)



अपील करते हुए कहा कि इससे ऐसी कठोर कार्रवाई से बचा जा सकता है।

के गरीब व होनहार युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में भेजने के लिए एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 'निःशुल्क आईएएस-पीसीएस आवासीय कोचिंग योजना' आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए अब राज्य के प्रतिभावान छात्रों को देश और प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं (वटहर और वटहरउ) की तैयारी पूरी तरह निशुल्क कराई जाएगी। 5 जुलाई की 10 हजार से अधिक अभ्यर्थी आजमाएंगे भाग्य इस योजना के अंतर्गत दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगामी 5 जुलाई 2026 को प्रदेश के सभी मंडलों में

डिजिटल लाइब्रेरी में लगी आग, मची भगदड़; लखनऊ जैसा हादसा अलीगढ़ में होने से बचा...धुआं भरने से घुटने लगा दम

अलीगढ़ के सरसौल चौराहा स्थित एस्पिरेन्ट डिजिटल लाइब्रेरी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया क्योंकि घटना के समय कोई मौजूद नहीं था।

(जीएनएस)। अलीगढ़। लखनऊ में हाल ही में हुए कोचिंग अग्निकांड के बाद भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भी जिले में बिना मान्यता के कोचिंग सेंटर संचालित हैं, जो सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई हैं। शुक्रवार सुबह सरसौल चौराहा पर नीवरी हाउस की दूसरी मंजिल पर संचालित ऐसी ही एस्पिरेन्ट डिजिटल लाइब्रेरी में अचानक आग लग गई। इससे अफरा-तफरी मच गई।

समय रहते दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अग्निशमन विभाग को सुबह करीब 7:36 बजे डायल-101 पर नीवरी हाउस की दूसरी मंजिल से धुआं निकलने की सूचना मिली थी। कुछ ही देर में अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में दो दमकल वाहन घटनास्थल पर पहुंचे।

मौके पर पहुंचने पर पता चला कि लाइब्रेरी के अंदर लगे सीलिंग फैन में शार्ट सर्किट होने से आग लग गई थी, जिसके कारण पूरी लाइब्रेरी धुएं से भर गई। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। दूसरी टीम ने स्मोक एग्जास्टर लगाकर इमारत से धुआं बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

राहत की बात यह रही कि घटना के समय लाइब्रेरी में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग में कुछ पंखे और लाइब्रेरी का सामान क्षतिग्रस्त हुआ है।

सीओ बन्नादेवी धनंजय सिंह ने बताया कि हादसे के समय लाइब्रेरी में कोई नहीं था। पंजीकरण भी नहीं मिला है। संबंधित विभागों से भी जानकारी कराई जा रही है।

क्या दिखावे की हो रही कार्रवाई लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद अलीगढ़ प्रशासन और विकास प्राधिकरण शहरभर में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच अभियान चला रहे हैं। शिक्षा विभाग ने भी बिना मान्यता चल रहे कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की, इसके बाद भी शहर में बिना मान्यता के ऐसे संस्थान हैं।

हैं। उनका उद्देश्य भूमि विवादों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करना और राजस्व न्याय प्रणाली को (जीएनएस)। लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए लगातार बड़े सुधार कर रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने सार्वजनिक भूमि से जुड़े मामलों के निस्तारण को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति और शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.

राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकारी और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पर जोर दे रहे

योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब तीन सदस्यीय स्पेशल बेंच करेगी सरकारी भूमि से जुड़े मामलों की सुनवाई, जानिए क्या है नई व्यवस्था

इस पहल से सरकारी और सार्वजनिक भूमि से जुड़े संवेदनशील मामलों का समय पर निस्तारण संभव होगा (जीएनएस)।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए लगातार बड़े सुधार कर रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने सार्वजनिक भूमि से जुड़े मामलों के निस्तारण को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. अब आरक्षित

श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति और शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.

राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकारी और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पर जोर दे रहे हैं. उनका उद्देश्य

नियमित कक्षाएं 1 अगस्त 2026 से प्रारंभ हो जाएंगी और यह विशेष शैक्षणिक सत्र 31 मई 2027 तक संचालित किया जाएगा। प्रदेश भर में स्थापित सात अत्याधुनिक आवासीय कोचिंग सेंटरों में कुल 865 चयनित अभ्यर्थियों को मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। सरकार ने इसमें एक विशेष व्यवस्था की की है, जिसके तहत 25 प्रतिशत सीटें उन छात्र-छात्राओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं जो लेटरल एंट्री के माध्यम से प्री परीक्षा (इंस्ट्रुक्शनल एंड) पहले ही

डिजिटल लाइब्रेरी में लगी यह आग सुरक्षा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े करती है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई क्या केवल दिखावे तक सीमित रही गई है।



15 संस्थान किए जा चुके हैं सील लखनऊ में हुई आग की घटना के बाद शहरभर में चलाए गए निरीक्षण अभियान के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर अब तक कुल 15 कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों को सील किया जा चुका है।

इनमें गेविटी कोचिंग सेंटर, कटारा कोचिंग सेंटर, अलीगढ़ काम्पिटिशन क्लासेज, शर्मा जी लाइब्रेरी (मेडिकल रोड), किंजा लाइब्रेरी और बंसल क्लासेज शामिल हैं।

प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट पाया गया है। जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय लाइब्रेरी बंद थी, जिसके कारण एक बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। आग से कुछ पंखे और लाइब्रेरी का अन्य सामान जल गया। - मुकेश कुमार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी

पोटों का गठन किया है, जो हर बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की करेंगी. इस पहल से सरकारी और सार्वजनिक भूमि से जुड़े संवेदनशील मामलों का समय पर निस्तारण संभव होगा, साथ ही पूरे प्रदेश में निर्णय प्रक्रिया में एकरूपता आएगी. वहीं, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस श्रेणी के सभी लंबित एवं नए प्रकरणों की पहचान कर उन्हें निर्धारित विशेष पीठ के पास दर्ज कराएं.

राजस्व व्यवस्था अधिक उत्तरदायी गौरतलब है कि योगी सरकार पहले ही राजस्व प्रशासन में व्यापक सुधारों की दिशा में कई सराहनीय पहल कर चुकी है। डिजिटल भू-अभिलेख, ऑनलाइन नामांतरण एवं अन्य राजस्व सेवाएं, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भूमि पैमाइश, पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया और सरकारी भूमि की सुरक्षा जैसे कदमों ने राजस्व व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी बनाया है.

लंबित और नए मुकदमों को अब तीन सदस्यीय विशेष पीठ के समक्ष ही पेश किया जाएगा. हर बुधवार को होगी मामलों की सुनवाई

अर्चना अग्रवाल ने ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज न्यायालय के लिए अलग-अलग तीन सदस्यीय विशेष

अर्चना अग्रवाल ने ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज न्यायालय के लिए अलग-अलग तीन सदस्यीय विशेष पीठ के समक्ष ही पेश किया जाएगा.

शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है. इसका मकसद इन संवेदनशील मामलों के निस्तारण में पारदर्शिता, न्यायिक गुणवत्ता और एकरूपता लाना है. इस

है. इसी के तहत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-9 के तहत मिली

शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है. इसका मकसद इन संवेदनशील मामलों के निस्तारण में पारदर्शिता, न्यायिक गुणवत्ता और एकरूपता लाना है. इस

वर्तमान दौर में जहां निजी संस्थानों में आईएएस-पीसीएस की तैयारी के नाम पर लाखों रुपये की फीस वसूली जाती है, वहीं गरीब परिवारों के बच्चों के लिए यह खर्च उठा पाना नामुमकिन होता है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह के अनुसार, योगी सरकार की इस पहल से वंचित और शोषित वर्ग के युवाओं में नया आत्मविश्वास जगा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सही दिशा मिलने से अब ये युवा भी ब्यूरोक्रेसी (प्रशासनिक सेवाओं) में अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज कराएंगे, जिससे आने वाले समय में समाज में एक बेहद सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

